भारत में रोजगार का निर्माण कैसे करें?

साभार: फाइनेंसियल एक्सप्रेस
(09 अक्टूबर, 2017)

राधिका कपूर
(आईसीआरईआर में अर्थशास्त्री)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

श्रम ब्यूरो की वार्षिक रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण (2015-16) के सबसे हालिया डेटा स्रोत से ज्ञात होता है कि भारत में रोजगार की समस्या बढ़ती जा रही है और यह सर्वेक्षण भारत में व्याप्त इस समस्या का व्यापक चित्र प्रदान करता है। जुलाई 2015 तक, सामान्य स्थिति (प्रमुख और सहायक स्थिति) द्वारा श्रमिकों की कुल संख्या 467.65 मिलियन थी, जो कि मार्च 2014 की तुलना में कम थी, जब रोजगार 480.38 मिलियन था। विनिर्माण क्षेत्र में विशेष रूप से रोजगार 51.4 करोड़ से घटकर 48.1 मिलियन हो गया। इस अवधि के दौरान रोजगार में उल्लेखनीय वृद्धि का एकमात्र क्षेत्र थोक और खुदरा व्यापार था, जहां रोजगार 43.7 करोड़ से बढ़कर 48.1 मिलियन हो गया।

2015-16 के बाद से हमारे पास रोजगार से संबंधित कोई भी आधिकारिक स्रोत का व्यापक डेटा मौजूद नहीं है। हालांकि, भारत के राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (एनएएस) का एक विश्लेषण, जो प्रमुख आर्थिक समेकन की रिपोर्ट करता है, दर्शाता है कि रोजगार सृजन का कार्य पहले की तुलना में और भी कठिन हो गया है। एनएएस ने निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई), सरकारी अंतिम उपभोग व्यय (जीएफसीई), सकल फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन (जीएफसीएफ) और नेट एक्सपोर्ट्स को एकत्रित करके जीडीपी का आंकलन किया गया था।

2015-16 और 2016-17 के बीच जीडीपी की वृद्धि दर धीमी होकर 7.1% हो गई थी, जो कि पिछले वर्ष में 8% थी। हालांकि 7% से अधिक विकास दर तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के प्रतिबिंबित होती है। वस्तुत: भारत में ये संख्याएं खपत व्यय से काफी अधिक होती हैं। 2016-17 में पीएफसीई और जीएफसीई क्रमश: 55% और जीडीपी का 10% था। जीएफसीई विशेष रूप से, 2015-16 और 2016-17 के बीच 20.8% तक तेजी से बढ़ी है, जो कि पिछले वर्ष में 3% के विपरीत था। इस अवधि के दौरान जीडीपी वृद्धि को बढ़ावा देने में जीएफसीई के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। दूसरी तरफ, निवेश, जो देश के विकास और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जीएफसीएफ के साथ निरंतर गिरावट 2013-14 में 32.5% जीडीपी से घटकर 2016-17 में 29.5% हो गई है। निर्यात वृद्धि भी धीमी रही है, यह सुझाव दे रहा है कि भारत श्रम-गहन विनिर्माण गतिविधियों के माध्यम से रोजगार के लिए अपना रास्ता निर्यात नहीं कर सकता।

खपत में उछाल लाकर विकास को बढ़ाया जा सकता है, जबकि निवेश करार करना स्थायी नहीं है। यह देखते हुए कि रोजगार सृजन में अभाव व्याप्त है, उपभोक्ताओं को अंतत: अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ सकती है। इसके अलावा, वित्तीय सीमाएं हैं जिनके लिए सरकार के खर्च में वृद्धि हो सकती है। जॉन स्टुअर्ट मिल की अंतर्दृष्टि है कि 'वस्तुओं की मांग श्रम की मांग नहीं हो सकती है', जो भारत में व्याप्त स्थिति को सच बनाती है, क्योंकि उपभोक्ता मांग में हुई वृद्धि रोजगार में रूपांतरित नहीं किया गया है। शायद यही कारण है कि 'उपभोक्ता' लोगों को रोजगार नहीं देते हैं, व्यवसाय करते हैं। वास्तविक आर्थिक सुधार के लिए, निजी निवेश में तेजी लाने की जरूरत है, क्योंकि इससे रोजगार और बेहतर विकास दोनों का निर्माण हो सकेगा।

एनएएस ने यह भी बताया कि 2016-17 में सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) में 6.6% की वृद्धि हुई थी, जो कि 2015-16 में 7.9% के विरोध में थी। जीवीए का एक क्षेत्रीय विघटन यह दर्शाता है कि जिन क्षेत्रों में अपेक्षाकृत तेजी से वृद्धि देखी गई थी, वे रोजगार-गहन नहीं थे। उदाहरण के लिए, क्षेत्र की वित्तीय, रीयल एस्टेट और पेशेवर सेवाएं और लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं में इस अवधि के दौरान लगभग 40% जीवीए विकास हुई थीं, लेकिन इसके बावजूद यह कुल रोजगार के 10% से भी कम था। दूसरी ओर कृषि कर्मचारियों के करीब आधे कार्यरत हैं, लेकिन जीवीए विकास का केवल 11.3% के लिए जिम्मेदार है।

आइए हम विनिर्माण क्षेत्र को विस्तार से समझते हैं, जो नौकरी सृजन के लिए एक प्रकाशस्तम्भ के रूप में कार्य करता है। वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान विनिर्माण जीवीए की वृद्धि के 21.2% के लिए जिम्मेदार है, जहाँ जीवीए 7.9% के साथ बढ़ा हुआ था। हालांकि, यह कुल रोजगार (2015-16) का केवल 10.2% के बराबर था। यह कार्य और जीवीए विकास के बीच डिस्कनेक्ट किया जा सकता है, जिसे इस प्रकार निम्नानुसार समझाया जा सकता है। एनएएस में विनिर्माण क्षेत्र को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र (पीसीएस) और घरेलू क्षेत्र। हालांकि यहाँ पद्धतिगत मतभेद हैं, इन दो समूहों ने क्रमश: पहले एनएआर श्रृंखला में संगठित और असंगठित क्षेत्रों के वर्गीकरण को बदल दिया है। यद्यपि हम 2016-17 के लिए पीसीएस और घरेलू क्षेत्र के लिए जीवीए डाटा को अलग नहीं करते हैं, लेकिन पिछले वर्षों के डेटा से पता चलता है कि यह पीसीएस ही है जो जीवीए (लगभग 87%) के असंतुलित हिस्से के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा, पीसीएस के भीतर भी, जीवीए की अधिक वृद्धि पूंजीगत उद्योगों जैसे कोक, पेट्रोलियम, रबर, रसायन और संबंधित उत्पादों और मशीनरी और उपकरण के निर्माण से हुई है। जबकि पीसीएस ने जीवीए के महत्वपूर्ण हिस्से के लिए इसे जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन यह घरेलू विनिर्माण क्षेत्र की तुलना में रोजगार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पीसीएस और घरेलू क्षेत्र के लिए रोजगार का कोई आधिकारिक अनुमान नहीं है। हालांकि, पीसीएस में रोजगार के लिए प्रॉक्सी के हालिया रिलीज किए गए वार्षिक सर्वेक्षण (2014-15) और घरेलू क्षेत्र में रोजगार के लिए प्रॉक्सी के गैर-कृषि उद्यमों (2015-16) के एनएसएस के अपरिवर्तनीय उद्यम सर्वेक्षण से डेटा का उपयोग करते हुए, हमें यह पता चलता है कि पूर्व में रोजगार बाद में 36 मिलियन की तुलना में लगभग 13 मिलियन था। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि पीसीएस में रोजगार सृजन की गति, जहां आवश्यक औपचारिक नौकरियां झूठ सामान होती हैं। 2013-14 और 2014-15 के बीच 300,000 से ज्यादा नौकरियों को जोड़ा जा रहा है।

सकल मांग और जीवीए के विभिन्न घटकों को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि भारत में विकास रोजगार-सघन नहीं है। भारत के औद्योगिक प्रदर्शन की प्रकृति, विशेष रूप से ऐसा है कि श्रमिक गहन उद्योग और उद्योग जो भारत के कम कुशल और अकुशल कर्मचारियों की बड़ी संख्या को अपने में शामिल कर सकता है, ने अभी तक बेहतर प्रदर्शन करने में असफल रहा है। यदि मौजूदा संरचनात्मक पैटर्न बने रहेंगे, तो नौकरी सृजन की चुनौती और गंभीर हो जाएगी। अधिक रोजगार की संभावना वाले क्षेत्रों में विकास और निवेश में तेजी लाने की तात्कालिकता को अगर महत्व नहीं दिया गया या इसमें की गयी देरी रोजगार के संकट और अधिक बढ़ा देगी।

अर्थशास्त्रियों का कहना है कि मौजूदा स्थिति को सुधारने के लिए सरकार को मूल तथ्यों पर ध्यान देते हुए कृषि, असंगठित खुदरा कारोबार व छोटे और लघु उद्योगों जैसे क्षेत्रों की सुरक्षा की दिशा आदि में ठोस पहल करनी होगी। देश में आजीविका के मौजूदा साधनों में से 99 फीसदी इन क्षेत्रों से ही आते हैं। 'इन क्षेत्रों कों सरकार के समर्थन की जरूरत है, नियमन की नहीं।' विशेषज्ञों का कहना है कि 21वीं सदी में देश को स्मार्ट गांव चाहिए, स्मार्ट शहर नहीं। प्राथमिकता के आधार पर ध्यान नहीं देने की स्थिति में आने वाले वर्षों में बेरोजगारी की यह समस्या और भयावह हो सकती है।

इससे संबंधित तथ्य

वर्ष 2011 की जनगणना से पता चलता है कि अर्थव्यवस्था में प्रतिवर्ष 7 प्रतिशत की औसत बढ़ोत्तरी हुई जबकि रोजगार की वृद्धि दर केवल 1.8 प्रतिशत ही रही।

समस्या के कारण क्या हैं?

- प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के बाद ही पढ़ाई छोड़ देने वाले विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा है। 2015 का आर्थिक सर्वेक्षण बताता है कि 15 वर्ष की आयु वाले बच्चों की संख्या मात्र 8 प्रतिशत है जो व्यवसायिक प्रशिक्षण ले रहे हैं या ले चुके हैं। देश के विकास के लिए सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली का विकसित एवं सुदृढ़ होना बहुत जरूरी है। वर्ष 2015-16 के बजट में शिक्षा के क्षेत्र में 3 प्रतिशत से 3.1 प्रतिशत की ही बढ़ोत्तरी की गई।
- 'मेक इन इंडिया' के तहत आई कंपनियां भारत में अपने उद्योग उत्पाद बेचने के उद्देश्य से लगाएंगी। ये उस तुलना में रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं कराएंगी, जबकि लघु और मध्यम दर्जे के उद्योग लगभग 40 प्रतिशत लोगों को रोजगार देते हैं। साथ ही भारतीय निर्मित सामान में 45 प्रतिशत तथा कुल निर्यात में 40 प्रतिशत का योगदान देते हैं। चूंकि इन उद्योगों के लिए सरकारी नीति बहुत सहायक नहीं है, इसलिए इन्हें बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है।
- एक सर्वे के अनुसार लगभग 95 प्रतिशत उद्योगों को बैंक के दायरे में लाने की जरूरत है। लघु उद्योग बैंकों से बहुत कम लाभ ले पा रहे हैं।
- सार्वजनिक बैंक इन लघु उद्योगों को ऋण देने की बजाए बड़ी कंपनियों को ऋण देते हैं।
- सरकार की वित्तीय नीति का लाभ बड़ी कंपनियों को भी अधिक मिलता है। वर्ष 2016-17 के बजट में कर (Tax) की लगभग साढ़े पाँच लाख करोड़ रुपये की छूट दी गई, जिसका ज्यादा लाभ बड़ी कंपनियों को ही मिला।
- मंद औद्योगिक विकास
- जनसंख्या में तीव्र वृद्धि
- सैद्धांतिक शिक्षा पर केंद्रित रहना
- कुटीर उद्योग में गिरावट
- कृषि मजदूरों के लिए वैकल्पिक रोजगार के अवसरों की कमी
- तकनीक का उन्नत न होना
- बेरोजगारी खत्म करने के संभव समाधान
- जनसंख्या पर नियंत्रण

संभावित समाधान

- **शिक्षा व्यवस्था:** भारत में शिक्षा प्रणाली कौशल विकास के बजाय सैद्धांतिक पहलुओं पर केंद्रित है। कुशल श्रमशक्ति उत्पन्न करने के लिए प्रणाली को सुधारना होगा।
- **औद्योगिकीकरण :** रोजगार के अधिक अवसर बनाने के लिए सरकार को औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने चाहिए।
- **विदेशी कंपनियां :** सरकार को रोजगार की अधिक संभावनाएं पैदा करने के लिए विदेशी कंपनियों की अपनी इकाइयों को देश में खोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
- **रोजगार के अवसर :** एक निश्चित समय में काम करके बाकि समय बेरोजगार रहने वाले लोगों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा किए जाने चाहिए।

संभावित प्रश्न

''चाहे किसी भी तरह का प्रचार अभियान क्यों न कर लिया जाये, लेकिन भारत में नौकरियों की समस्या के लिए त्वरित सुधार संभव नहीं हैं।'' **इस कथन के संदर्भ में वर्तमान में भारत में रोजगार में आयी कमी के उत्तरदायी कारणों की चर्चा करें।**

"The present government has so far formulated many campaigns and schemes to strengthen the problem of unemployment in the country. But despite this, the problem is not being solved." In the context of this statement, discuss the reasons for the lack of employment in India. **(200 WORD)**